प्रेम गिरि

बनाम

'राजस्थान का राज्य

(आपराधिक अपील सं। 2017 के 2188) दिसंबर 14,2017

[आर. के. अग्रवाल और अभय मनोहर सप्रे, जेजे।]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

5.438-प्रत्याशित जमानत-की अस्वीकृति। उच्च न्यायालय द्वारा-अपील पर, आयोजितः उच्च न्यायालय जमानत को अस्वीकार करने के लिए कोई कारण बताने में विफल रहा-इस प्रकार, अपने न्यायिक दिमाग को लागू नहीं किया और एक कारण और घुड़सवार तरीके से आदेश पारित किया-मामले को नए सिरे से तय करने के लिए उच्च न्यायालय को भेजा गया कानून के अनुसार-जमानत।

अपील की अनुमति देते हुए और मामले को उच्च न्यायालय भेजते हुए, न्यायालय ने:

माना: 1. उच्च न्यायालय अपीलकर्ता की जमानत अर्जी खारिज करने का कोई कारण बताने में विफल रहा। सामान्य टिप्पणियों को जोड़ते हुए कहें कि "मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मुझे याचिकाकर्ता को जमानत देना उचित नहीं लगता" कभी भी जमानत याचिका को खारिज करने के लिए न्यायिक तर्क की आवश्यकता नहीं हो सकती है, चाहे वह इसके तहत दायर की गई हो। सी आर पी सी की धारा 438 या धारा 439. उच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया और बहुत ही लापरवाही और लापरवाही भरे तरीके से विवादित आदेश पारित कर दिया। जमानत आवेदन पर नए सिरे से उसके गुण-दोष के आधार पर और कानून के अनुसार निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेजना उचित और उचित होगा। [पैरा 7, 8, 9 और 12) [489-ई-ई; 490-जी]

कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन @पप्पू यादव और अन्य। (2004) 7 एससीसी 528-पर निर्भर। केस लॉ संदर्भ।

(2004) 7 एससीसी 528 पर भरोसा किया। पैरा

क्रिमिनल अपीलीय न्यायाधिकरणः आपराधिक अपील 2017 का नंबर. 218।

जोधपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय के 22.11.2017 के निर्णय और आदेश से। आपराधिक विविध जमानत संख्या 9471/2017।

अपीलार्थी के लिए पुनीत जैन, सुश्री क्रिस्टी जैन, सुश्री, अंकिता गुप्ता, प्रियल जैन, अभिनव गुप्ता, सुश्री प्रतिभा जैन, सलाहकार।

न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय

अभय मनोहर सप्रे, जे. 1. दी गई छुट्टी।

2. यह अपील 22.11.2017 के अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जो जोधपुर में राजस्थान के उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक न्यायालय द्वारा पारित की गई है। आपराधिक विविध। 2017 की जमानत संख्या 9.9471 जिसमें उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 438 (बाद में "संहिता" के रूप में संदर्भित) के तहत दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

3. मामले के तथ्य एक संकीर्ण कम्पास में निहित हैं। हालांकि, उन्हें मामले में शामिल लघु मुद्दे की सराहना करने के लिए इन्फ्रा का उल्लेख करने की आवश्यकता है।

4. अपीलार्थी ने भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 143,341,323,308,332 और 353 के तहत दंडनीय अपराधों के कमीशन के साथ अपनी गिरफ्तारी की अपील की (बाद में इसे "आईपीसी" के रूप में संदर्भित किया गया)। 332/2017 पुलिस स्टेशन जैतारण, जिला में पंजीकृत। पाली ने राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष संहिता की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत देने के लिए एक आवेदन दिया। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने लगाए गए आदेश को खारिज कर दिया, जैसा कि आवेदक द्वारा इस न्यायालय में विशेष अवकाश के माध्यम से इस अपील को दायर करने के लिए दिया गया है।

5. लागू किया गया आदेश इस प्रकार हैः "यह जमानत याचिका सीआरपीसी की धारा 438 के तहत पुलिस स्टेशन जैतारण, जिला पाली में दर्ज एफआईआर संख्या 332/2017 के धारा 143, 341, 323, 308, 332 एवं 353 आईपीसी संबंध में दायर की गई है।

याचिकाकर्ता और विद्वान जनता के विद्वान वकील को सुना अभियोजक राज्य की ओर से विद्वान वकील के रूप में उपस्थित हुए शिकायतकर्ता के लिए और प्रासंगिक का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया मटेरिया! रिकॉर्ड पर उपलब्ध कराया गया.. मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, लेकिन गुणों पर कोई राय व्यक्त किए बिना और मामले के दोषों के आधार पर, मैं याचिकाकर्ता(ओं) को जमानत पर रिहा करना उचित और उचित नहीं मानता।

इसलिए यह जमानत अर्जी खारिज की जाती है।”

6. हमने अपीलकर्ता के विद्वान वकील वकील को सुना है और मामले के रिकॉर्ड का दुरुपयोग किया है। हमारे विचार में, उस आदेश को ध्यान में रखते हुए, जिसे हम पारित कर रहे हैं, इस अपील में राज्य को सुनने के लिए राज्य को नोटिस जारी करना बहुत कम आवश्यक नहीं है।

7. अधिरोपित आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि यह दिखाने के लिए कि एकल न्यायाधीश अपीलकर्ता की जमानत याचिका को खारिज करने के लिए कोई कारण बताने में विफल रहा।

8. सामान्य अवलोकन कि "मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, याचिकाकर्ता को जमानत देना उचित नहीं माना जाता है" कभी भी जमानत याचिका की अस्वीकृति के लिए आवश्यक न्यायिक तर्क से कम नहीं हो सकता है कि क्या यह धारा 438 या संहिता की धारा 439 के तहत दायर किया गया है ।

9. हम यह देखने के लिए विवश हैं कि सीखा एकल न्यायाधीश ने अपने न्यायिक दिमाग को लागू नहीं किया और बहुत ही आकस्मिक और घुड़सवार तरीके से लगाए गए आदेश को पारित कर दिया। यह न्यायालय जमानत के लिए आवेदन का निर्णय करते समय उच्च न्यायालय के ऐसे आकस्मिक दृष्टिकोण की गणना नहीं कर सकता है।

10, बार-बार, इस न्यायालय ने जमानत देने या अस्वीकार करने पर विचार करते समय कारणों को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। कल्याण चंद्र सरकार बनाम राजेश रंजन @पप्पू यादव और अनर के फैसले के पारस 11 और 12 में इस न्यायालय ने जो कुछ भी किया है, उसे पुनः प्रस्तुत करना उपयुक्त है। (2004) इस मुद्दे पर 7 एससीसी 528।

"11, जमानत देने या देने से इनकार करने के संबंध में कानून बहुत अच्छा सुलझा लिया है। जमानत देने वाली अदालत को अपना अभ्यास विवेकपूर्ण तरीके से विवेक और निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए। हालांकि जमानत देने के चरण में साक्ष्य की एक विस्तृत परीक्षा और विस्तृत दस्तावेज मामले की योग्यता की आवश्यकता नहीं है, प्रथम दृष्टया ऐसे आदेशों के कारणों को इंगित करने की आवश्यकता है यह निष्कर्ष निकालते हुए कि जमानत क्यों दी जा रही है, विशेष रूप से जहां अभियुक्त पर गंभीर अपराध करने का आरोप है। ऐसे कारणों से रहित कोई भी आदेश दिमाग का उपयोग न करने से प्रभावित होगा। जमानत देने वाली अदालत के लिए जमानत देने से पहले अन्य परिस्थितियों के अलावा निम्नलिखित कारकों पर भी विचार करना आवश्यक है; वे हैं: (ए) दोषसिद्धि के मामले में आरोप की प्रकृति और सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्य की प्रकृति। (बी) गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका या शिकायतकर्ता को खतरे की आशंका। (सी) आरोप के समर्थन में अदालत की प्रथम दृष्टया संतुष्टि। (राम गोविंद उपाध्याय बनाम सुदर्शन सिंह, (2002) 3 एससीसी 598 और पूरन बनाम रामबिलास, (2001) 6 एससीसी 338 देखें) 12, उन मामलों के संबंध में जहां पहले जमानत आवेदन खारिज कर दिए गए हैं, अदालत पर एक और जिम्मेदारी है उन आधारों पर गौर करते हुए जमानत देने के लिए बाद के आवेदन पर विचार करना जिन पर पहले जमानत आवेदन खारिज कर दिए गए हैं और इस तरह के विचार के बाद यदि अदालत की राय है कि जमानत दी जानी है तो उक्त अदालत को विशिष्ट कारण बताना होगा कि क्यों ऐसी पूर्व अस्वीकृति के बावजूद जमानत के लिए बाद की अर्जी मंजूर की जानी चाहिए। (राम गोविंद उपाध्याय देखें)"

11. हमारी सुविचारित राय में, एकल न्यायाधीश इस न्यायालय द्वारा पूर्व उद्धृत कानून पर ध्यान देने में विफल रहे और इस प्रकार विवादित आदेश पारित करने में गलती की। उन्होंने न तो मामले के तथ्य बताए, न ही दोनों पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील की दलीलों का उल्लेख किया और न ही अपने तर्क का उल्लेख किया कि वह अपीलकर्ता को अग्रिम जमानत देना उचित क्यों नहीं मानते। यह सबसे कम बात थी, जिसे आदेश पारित करते समय एकल न्यायाधीश से ध्यान में रखने की अपेक्षा की गई थी।

12. इस मामले में उत्पन्न होने वाली ऐसी स्थिति में, हम इस अपील में अपीलकर्ता के मामले को उसकी योग्यता के आधार पर विचार करने के बजाय, उसकी योग्यता के आधार पर और कानून के अनुसार जमानत की अर्जी को नए सिरे से तय करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेजने के लिए उचित और उचित मानते हैं।

13. हालाँकि, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हम अपीलकर्ता के मामले के गुण-दोष में नहीं गए हैं, जिसने जमानत के आवेदन को योग्यता के आधार पर नए सिरे से तय करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेजने के लिए एक राय बनाई है और इसलिए, उच्च न्यायालय निर्णय करेगा जमानत आवेदन योग्यता के अलावा हमारी किसी भी टिप्पणियों से प्रभावित नहीं है जमानत आवेदन पर निर्णय लेने के तरीके के बारे में हमने क्या कहा है।

14. पूर्वगामी चर्चा के मद्देनजर, अपील सफल होती है और अनुमति दी जाती है। प्रभावित आदेश को अलग रखा गया है और अपीलकर्ता की जमानत याचिका को उसकी योग्यता के आधार पर नए सिरे से तय करने के लिए मामला उच्च न्यायालय को भेज दिया गया है। ,

अपील की अनुमति दी।

सर्वम द्विवेदी